भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

84. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में न्यनूतम मजदूरी के निर्धारण के मानदंड/सूत्र क्या हैं;

(ख) क्या देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए बनाए गए फार्मूले में काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार न्यनूतम मजदूरी फार्मूला को जीवन निर्वाह मजदूरी से प्रतिस्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में हितधारकों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(च) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कामगारों की मजदूरी को महंगाई दर के साथ जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (च): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी दर में अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरी के मूल दर और जीवन-निर्वाह भत्ते की लागत शामिल किए जाने का प्रावधान है।

केंद्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के प्रभावों से बचाने के लिए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर निर्वाह लागत भत्ते जिसे परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) कहा जाता है, में प्रत्येक छह महीने में संशोधन करती है जो 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी होती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सम्मिलित किया गया है और इसमें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संहिता में न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत यथाउपबंधित अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की सीमित प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाया गया है।

*****